



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

No. 351]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्टूबर, 2015

सं.टीएमपी/4/2004-सामान्य.— पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं. 8/(15)2015-टीएमपी दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, इस प्राधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 12 जनवरी 2005 द्वारा अधिसूचित तटीय रियायत नीति में आंशिक रूप से संशोधन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य

आदेश

(अक्टूबर 2015 के 5वें दिन पारित)

अधिनियम की धारा 42(3) के अधीन प्राधिकृत सभी महापत्तन न्यासों और निजी प्रचालकों में प्रभारित तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोत संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरों के निर्धारण हेतु (तत्कालीन) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) में भारत सरकार द्वारा अपने संप्रेषण सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 01 जनवरी 2005 द्वारा इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन नीति निदेश जारी किया था।

2. तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोतों से संबंधित प्रभारों के लिए रियायती दरें निर्धारित करने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन (तत्कालीन) एमएसआरटीएच द्वारा जारी किए गए नीति निदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने सामान्य शर्तों का एक सेट शामिल करते हुए सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनल प्रचालकों के दरमानों में संशोधन करने के लिए 7 जनवरी 2005 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 3 के अधीन 12 जनवरी 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

3.1. तत्पश्चात, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर (तत्कालीन) एमएसआरटीएच ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 9 मार्च 2005 द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 जनवरी 2005 के प्रचालन से लौह अयस्क और लौह अयस्क गुट्टिकाओं को छूट प्रदान करने के लिए इस प्राधिकरण को निदेश दिया था।

3.2. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेश के अनुपालन में, इस प्राधिकरण ने तटीय व्यापार के लिए रियायती कार्गो संबंधित प्रभारों से लौह अयस्क और लौह अयस्क गुट्टिकाओं को अलग रखने के लिए अपना पूर्ववर्ती आदेश सं. टीएमपी/4/2004-सामान्य दिनांक 7 जनवरी 2005 संशोधित किया था।

4. 01 जनवरी 2005 के नीति निदेश में बताया गया है कि योजना दो वर्षों की अवधि के लिए पाइलट आधार पर शुरू की गई थी जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। एमएसआरटीएच ने अपने संप्रेषण सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 22 अप्रैल 2009 द्वारा बताया था कि तटीय कार्गो/कंटेनर/पोत के लिए रियायती प्रशुल्क की समीक्षा पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा विचाराधीन है। समीक्षा किए जाने और परिणामस्वरूप भिन्न नीति निर्धारण तक इस प्राधिकरण को तटीय कार्गो/कंटेनर/पोतों के लिए तटीय दरों से संबंधित मौजूदा नीति निदेश के साथ जारी रखने का निदेश दिया गया था। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी की गई तटीय रियायत नीति अभी भी प्रभावी है।

5.1. एमओएस ने अब अपने पत्र सं. 8/(15)2015-टीएमपी दिनांक 17 सितम्बर 2015 द्वारा इस प्राधिकरण को निदेश जारी किया है कि उसके पत्र दिनांक 1/3 जनवरी 2005 और 9 मार्च 2005 द्वारा जारी की गई तटीय रियायत नीति को इस सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाए कि तटीय पोतों हेतु दरों के पुनर्विवरण में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के विनिमय दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लिया जाए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

5.2. एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 17 सितम्बर 2015 में कहा है कि:

(i) टीएमपी द्वारा अधिसूचित और उसके पत्र सं. टीएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस दिनांक 29 मई 2015 द्वारा परिचालित महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति कार्यान्वित करने के लिए कार्य दिशानिर्देश, 2015 में, दिशानिर्देशों का पैरा 10 पोत संबंधित प्रभारों से संबंधित है जोकि तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी 2005 और 9 मार्च 2005 में उन शामिल के अनुसार है।

(ii) उक्त निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सामान्य संशोधन के समय प्रचलित विनिमय दर के लिए डॉलर मूल्यवर्गित पोत प्रभारों और कंटेनर संबंधित प्रशुल्क का पुनर्विवरण स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ पत्तनों ने बताया है कि दशक में प्रचलित विनिमय दर के लिए तटीय पोत दरों के गैर-पुनर्विवरण के लेखा पर, तटीय पोतों द्वारा आनंदित रियायत उसके विदेशगामी कार्टर पार्ट के 40 प्रतिशत से अधिक है।

प्रत्येक समय विदेशी पोत संबंधित प्रभारों के 60 प्रतिशत पर तटीय पोत संबंधित प्रभारों को बनाए रखने के लिए और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के विनिमय दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लेने के लिए एक सुझाव प्रकट हुआ है कि टीएमपी द्वारा यथा अधिसूचित महापत्तन न्यास हेतु प्रशुल्क नीति, 2015 कार्यान्वित करने के लिए कार्य दिशानिर्देशों का खंड 10.1.2 निम्नलिखित खंड से परिवर्तित किया जा सकता है:-

“10.1.2. तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार विदेशगामी पोतों हेतु के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, यह प्रभार केवल भारतीय रुपयों में वसूल किए जाएंगे।”

(iii) सरकार द्वारा उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया गया है और इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) इसके साथ, तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्रों सं. पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी 2005 और 9 मार्च 2005 द्वारा जारी किए गए निर्देश इस सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किए जाएंगे कि तटीय पोतों के लिए दरों का पुनर्विवरण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के विनिमय दर उतार-चढ़ाव लेखा में लिया जा सके ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तदनुसार, सभी तटीय पोतों के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य पोतों के लिए लागू तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और ये प्रभार लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में संग्रहीत किया जाएगा।

5.3. उपर्युक्त के मद्देनजर, इस प्राधिकरण को निदेश दिया है कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 42(3) के अधीन प्राधिकृत सभी महापत्तन न्यासों और निजी प्रचालकों में प्रसारित तटीय पोत संबंधित प्रभारों और तटीय कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों को उचित ढंग से तत्काल निर्धारित करे।

6.1. चूंकि पात्र तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधित प्रभार तटीय रियायत नीति में यथा परिकल्पित महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के मौजूदा दरमानों में विदेशी कार्गो के लिए लागू तदनुसूची दर के 60 प्रतिशत पर रुपए रुप में निर्धारित किए गए हैं और विनिमय दर भिन्नता के लेखा पर पुनर्विवरण की कोई संलिप्तता नहीं है, महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनलों के मौजूदा दरमानों में तटीय कार्गो हेतु निर्धारित प्रशुल्क में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

6.2. कंटेनर संबंधित प्रभारों के संबंध में, कुछ कंटेनर टर्मिनल प्रचालकों जैसे चेन्नई पत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन पत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई पत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमानों में कुछ कंटेनर संबंधित प्रशुल्क विदेशी कंटेनर के लिए अमेरिकी डॉलर में निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, इन कंटेनर टर्मिनल प्रचालकों के दरमानों में निर्धारित प्रासंगिक प्रशुल्क मदों के लिए तटीय दरों में एमओएस द्वारा अब जारी किए गए निदेश के मद्देनजर संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

6.3. इस प्रकार, संक्षेप में, महापत्तन न्यासों के मौजूदा दरमानों में तटीय श्रेणी के लिए दरों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई तटीय रियायत नीति में आंशिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी जहां पोत संबंधित प्रभार विदेशगामी पोतों के लिए अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित किए गए हैं। महापत्तन न्यास में प्रचालन कर रहे बीओटी प्रचालकों के लिए जिनके मौजूदा दरमान पोत संबंधित प्रभारों के साथ-साथ कंटेनर संबंधित प्रभार अमेरिकी डॉलर में निर्धारित करते हैं, उनके दरमानों में भी उपयुक्ततः संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

7.1. एमओएस का निदेश तटीय पोत संबंधित प्रभारों और तटीय कार्गो/कंटेनर संबंधित प्रभारों के तत्काल निर्धारण की अपेक्षा करता है। यदि तटीय पोत संबंधित प्रभार और तटीय कंटेनर संबंधित प्रभार तदनुसूची प्रशुल्क मदों के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग पर प्रचलित विनिमय दर लागू करते हुए निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसी निर्धारित तटीय दरें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के मद्देनजर दूसरे दिन के लिए भी वैध नहीं रहेंगी। अतः, सरकारी निदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त टिप्पणी निर्धारितकरना उपयुक्त पाया गया है। तदनुसार, नीचे दी गई टिप्पणियां महापत्तन न्यासों और वहां पर बीओटी प्रचालकों द्वारा उपयुक्ततः शामिल किए जाने के लिए उनके तत्संबंधी दरमानों में निर्धारित की गई हैं:

(क) सामान्य शर्तें:

“(i). तटीय पोत के लिए पोत संबंधित प्रभारों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के विनिमय दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लिया जाना चाहिए ताकि तटीयपोत के लिए पोत संबंधित प्रभार अन्य विदेशगामी पोतों के लिए तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हों। इसके अलावा, ये प्रभार लागू विनिमय दर में केवल भारतीय रुपयों में संग्रहीत किए जाएंगे।

(ii). कंटेनर संबंधित प्रभारों के संबंध में जो विदेशी कंटेनरों के लिए अमेरिकी डॉलरों में मूल्यवर्गित किए गए हैं, तटीय कंटेनर के लिए प्रशुल्क अन्य विदेशी कंटेनरों हेतु तदनुसूची प्रभारों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, ये प्रभार लागू विनिमय दर में केवल भारतीय रुपयों में संग्रहीत किए जाएंगे।”

(ख) पोत संबंधित प्रभारों की अनुसूची में, तटीय पोतों के लिए निर्धारित दरें निम्नलिखित टिप्पणी से परिवर्तित की गई हैं:

“तटीय पोत के लिए दर विनिमय दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लेते हुए (जक्सटापोस्ट विदेशगामी पोत हेतु दर के) 60 प्रतिशत तक परिगणित किया गया है।”

(ग) कंटेनर संबंधित प्रभारों की अनुसूची में जहां दरें विदेशी श्रेणी के लिए डॉलरों में मूल्यवर्गित की गई हैं, उन मामलों में तटीय कंटेनर हेतु दरों को निम्नलिखित से परिवर्तित किया गया है:

“तटीय कंटेनर के लिए दर विनिमय दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लेते हुए (जक्सटापोस्ट विदेशगामी पोत हेतु दर के) 60 प्रतिशत तक परिगणित किया गया है।”

7.2. उपर्युक्त (ख) और (ग) के संबंध में एक उदाहरण अनुबंध रूप में संलग्न किया गया है।

8.1. सभी महापत्तन न्यासों को तदनुसार अपने दरमान संशोधित करने का निदेश दिया जाता है।

8.2. महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे निजी टर्मिनल प्रचालकों के मामले में जिनके मौजूदा दरमानों में विदेशी श्रेणी के लिए पोत संबंधित प्रभार और/अथवा कंटेनर संबंधित प्रभार अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्यवर्गित किए गए हैं, उन्हें अपने दरमान तदनुसार संशोधित करने का निदेश दिया जाता है।

9. पत्तनों/टर्मिनलों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, एमओएस के निदेश के आधार पर यहाँ ऊपर आदेशित तटीय पोतों/कंटेनरों के लिए आंशिक रूप से संशोधित प्रावधान 1 नवम्बर 2015 से लागू होंगे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञा. III/4/असा./143/2015(232)]

अनुबंध

मौजूदा दरमानों में निर्धारित तटीय पोत/तटीय कंटेनर दरों से परिवर्तित करने के संबंध में एक उदाहरण।

(i) (क) मान लीजिए मौजूदा दरमानों में निर्धारित एक पोत संबंधित प्रशुल्क मद निम्नवत् है:-

क्र.सं.	पोतों के प्रकार हेतु पत्तन देयताएं	दर प्रति जीआरटी/प्रति पोत प्रवेश	
		विदेशगामी पोत (अमेरिकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
1.	टैंकर (पत्तन ऑयल बर्थों पर आने वाले कच्चा तेल और पीओएल पोत)	0.377	10.08
2.	एसबीएम और एसटीएस में कच्चा तेल टैंकर	0.377	10.08

(ख) इसे निम्नवत् परिवर्तित किया जाएगा:

क्र.सं.	पोतों के प्रकार हेतु पत्तन देयताएं	दर प्रति जीआरटी/प्रति पोत प्रवेश	
		विदेशगामी पोत (अमेरिकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
1.	टैंकर (पत्तन ऑयल बर्थों पर आने वाले कच्चा तेल और पीओएल पोत)	0.377	तटीय पोत के लिए दर विनियम दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लेते हुए (जक्सटापोस्ट विदेशगामी पोत हेतु दर के) 60 प्रतिशत तक परिगणित किया गया है।
2.	एसबीएम और एसटीएस में कच्चा तेल टैंकर	0.377	

(ii) (क) मान लीजिए एक कंटेनर संबंधित प्रशुल्क जो विदेशी कंटेनर के लिए अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित किए जाते हैं और मौजूदा दरमानों में तदनुरूपी तटीय कंटेनर दर निम्नवत् है:-

विवरण	विदेशगामी पोत (अमेरिकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
प्रति एफसीएल कंटेनर		
- 20' लम्बाई से अनाधिक	14.64	369.04
- लम्बाई में 20' से अधिक और 40' तक	21.96	553.32
- 40' लम्बाई से अधिक	29.28	737.92

(ख) इसे निम्नवत् परिवर्तित किया जाएगा:

विवरण	विदेशगामी पोत (अमेरिकी डॉलर में)	तटीय पोत (रु. में)
प्रति एफसीएल कंटेनर		तटीय कंटेनर के लिए दर विनियम दर उतार-चढ़ाव को लेखा में लेते हुए (जक्सटापोस्ट विदेशगामी पोत हेतु दर के) 60 प्रतिशत तक परिगणित किया गया है।
- 20' लम्बाई से अनाधिक	14.64	
- लम्बाई में 20' से अधिक और 40' तक	21.96	
- 40' लम्बाई से अधिक	29.28	

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2015

No. TAMP/4/2004-Genl..— In compliance of a direction issued by the Ministry of Shipping, Government of India vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 and in exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby partially amends the coastal concession policy notified by this Authority vide earlier vide Order No.TAMP/4/2004-Genl dated 12 January 2005 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

ORDER

(Passed on this 5th day of October, 2015)

The Government of India in the (then) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (MSRTH) vide its communication No.PR-14019/29/2001-PG dated 01 January 2005 had issued a policy direction to this Authority under Section 111 of the MPT Act, 1963 to prescribe concessional rates for coastal cargo/ containers/ vessels related charges levied at all major port trusts and private operators authorized under section 42(3) of the Act.

2. In compliance of a policy direction issued by the (then) MSRTH under section 111 of the Major Port Trusts Act to prescribe concessional rates for coastal cargo/containers/vessels related charges, this Authority passed an Order on 7 January 2005 to amend the Scale of Rates of all the major port trusts and private terminal operators by inserting a set of general conditionalities. This Order was notified in the Gazette of India on 12 January 2005 under Gazette No.3.

3.1. Subsequently, the (then) MSRTH based on the representation made by the Visakhapatnam Port Trust (VPT) directed this Authority to exempt iron ore and iron ore pellets from the operation of the Order dated 7 January 2005 passed by this Authority vide MSRTH letter No.PR-14019/29/2001-PG dated 9 March 2005.

3.2. In compliance of the policy direction issued by the Government of India, this Authority amended its earlier Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 7 January 2005 to exclude iron ore and iron ore pellets from the concessional cargo related charges for coastal trade. This Order was notified in the Gazette of India on 22 March 2005.

4. The policy direction of 01 January 2005 stated that the scheme was introduced on pilot basis for two year period after which it will be reviewed. The MSRTH vide its communication No.PR-14019/29/2001-PG dated 22 April 2009 stated that the review of the concessional tariff for coastal cargo/ container/ vessel is under consideration by the Department of Shipping. Till the review is done resulting in a different policy prescription this Authority was directed to continue with the existing policy direction relating to coastal rates for coastal cargo/ container/ vessels. Thus, the coastal concession policy issued by the Government of India is still in force.

5.1. The MOS has now vide its letter No.8/(15)2015-TAMP dated 17 September 2015 has issued a direction to this Authority partially modifying the coastal concessional policy issued by it vide its letter dated 1/3 January 2005 and 9 March 2005 to the extent that restatement of rates for coastal vessels should take into account the exchange rate fluctuation of the Indian Rupee Vs the US \$ so that vessel related charges for all coastal vessels do not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.

5.2. The MOS in its letter dated 17 September 2015 has stated that:

- (i) In the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts 2015 notified by TAMP and circulated vide their letter No.TAMP/21/2009-WS dated 29 May 2015, Para 10 of the Guidelines relate to vessel related charges which are in line with those contained in the then Ministry of Shipping, Road Transport & Highways letters No.PR-14019/29/2001-PG dated 1 / 3 January 2005 and 9 March 2005.
- (ii) As per the said instructions restatement of dollar denominated vessel charges and container related tariff to the exchange rate prevailing at the time of each general revision is not allowed. Some of the ports have pointed out that on account of non-restatement of coastal vessel rates to the prevailing exchange rate over decade, the concession enjoyed by coastal vessels is more than 40% of their foreign going Counterpart.

In order to keep the coastal vessel related charges at 60% of the foreign vessel related charges at all times and to account for the exchange rate fluctuation of the INR vs the US \$ a suggestion emerged that clause 10.1.2. of the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trust, 2015 as notified by the TAMP be replaced with the following clause:

"10.1.2. Vessel-related charges for Coastal vessels will not exceed 60% of that for foreign-going vessels. Further, these charges shall be collected in Indian Rupees only."

- (iii) The above suggestion has been considered by the Government and it has been decided to accept the same.
- (iv) With this, the instructions issued by the then Ministry of Shipping, Road Transport & Highways letters No.PR-14019/29/2001-PG dated 1/ 3 January 2005 and 9 March 2005 would get partially modified to the extent that restatement of rates for coastal vessels should take into account the exchange rate fluctuation of the Indian Rupee vs the US \$ so that vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels. Accordingly, vessel related charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges applicable for other vessels and these charges will be collected in Indian Rupees at the applicable exchange rate.

5.3. In view of the above, the MOS has directed this Authority to appropriately prescribe the coastal vessel related charges and coastal cargo/ container related charges levied at all Major Port Trusts and private operators authorized under Section 42(3) of the Major Port Trusts Act, 1963 immediately.

6.1. Since the cargo related charges for eligible coastal cargo are prescribed in rupee terms at 60% of the corresponding rate applicable for foreign cargo in the existing Scale of Rates of Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat as envisaged in the coastal concession policy and there is no involvement of restatement on account of

exchange rate variation, no modification is required in the tariff prescribed for coastal cargo in the existing Scale of Rates of Major Port Trusts and Private terminals operating thereat.

6.2. As regards container related charges, in the Scale of Rates of few Container Terminal operators like the Chennai Container Terminal Private Limited and Chennai International Terminal Private Limited operating in Chennai Port Trust, India Gateway Terminal Private Limited operating in Cochin Port Trust, Indira Container Terminal Pvt. Ltd. operating in Mumbai Port Trust and PSA SICAL Terminals Private Limited operating in V.O. Chidambaranar Port Trust some of the container related tariff are prescribed in US\$ for foreign container. Hence, the coastal rates for the relevant tariff items prescribed in the Scale of Rates of these container terminal operators will require modification in view of the direction now issued by the MOS.

6.3. Thus, in short, the partial amendment in the coastal concession policy issued by the Government as regards application of rates for coastal category will require amendment in the existing Scale of Rates of Major Port Trusts where the vessel related charges are denominated in US dollar for the foreign going vessel. For BOT operators operating at Major Port Trust whose existing Scale of Rates prescribes the vessel related charges as well as container related charges in US dollar, their Scale of Rates will also require to be amended suitably.

7.1. The direction of the MOS requires immediate prescription coastal vessel related charges and coastal cargo/container related charges. If coastal vessel related charges and coastal container related charges are prescribed applying the prevailing exchange rate on the US \$ denomination for corresponding tariff items, such prescribed coastal rates will not remain valid even for the second day in view of fluctuation in the exchange rate. Therefore, it is found appropriate to prescribe a suitable note to give effect to the Government direction. Accordingly, the notes as given below are prescribed to be suitably incorporated by the Major Port Trusts and BOT operators thereat in their respective Scale of Rates:

(A) General conditions:

- “(i) *Vessel related charges for coastal vessel should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee Vs US \$ so that vessel related charges for coastal vessels shall not exceed 60% of the corresponding charges for other foreign going vessels. Further, these charges will be collected in Indian Rupees only at the applicable exchange rate.*
- “(ii) *As regards the Container related charges which are denominated in US dollars for the foreign containers, the tariff for coastal container shall not exceed 60% of the corresponding charges for other foreign containers. Further, these charges will be collected in Indian Rupees only at the applicable exchange rate.*”

(B) In the Schedule of Vessel Related Charges, the rates prescribed for coastal vessels is replaced with the following note:

“Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign-going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation.”

(C) In the Schedule of Container Related Charges where rates are denominated in dollars for the foreign category, in those cases the rates for coastal container is replaced with the following:

“Rate for coastal container is upto 60% (of the rate juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation.”

7.2. An illustration as regards (B) and (C) above is attached as **Annex**.

8.1. All the Major Port Trusts are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

8.2. In the case of private terminal operators operating in the Major Port Trusts in whose existing SOR the vessel related charges and/ or container related charges for foreign category are denominated in US dollar terms, they are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

9. Recognising the lead time required for implementation by ports/ terminals, the partially amended provisions for coastal vessels/ container ordered hereinabove based on the direction of the MOS shall come into effect from 1 November 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2015(232)]

Annex**An illustration as regards replacing the coastal vessel/ coastal container rates prescribed in the existing Scale of Rates.**

- (i) (a) Suppose vessel related tariff item prescribed in the existing Scale of Rates is as follows:

Sl. No.	Port Dues for Type of Vessels	Rate per GRT/ per entry of vessel	
		Foreign-going vessel (in US \$)	Coastal vessel (in `)
1.	Tanker (Crude oil & POL Vessels calling at Port Oil Berths)	0.377	10.08
2.	Crude Oil Tanker at SBM & STS	0.377	10.08

- (b) This is to be replaced as follows:

Sl. No.	Port Dues for Type of Vessels	Rate per GRT/ per entry of vessel	
		Foreign-going vessel (in US \$)	Coastal vessel (in `)
1.	Tanker (Crude oil & POL Vessels calling at Port Oil Berths)	0.377	Rate for coastal vessel is upto 60% (of the rate for foreign-going vessel juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation.
2.	Crude Oil Tanker at SBM & STS	0.377	

- (ii) (a) Suppose container related tariff which are denominated in US \$ for foreign container and the corresponding coastal container rate in the existing Scale of Rates is as follows:

Particulars	Foreign-going vessel (US \$)	Coastal vessel (in `)
Per FCL Container		
- Not exceeding 20' in length	14.64	369.04
- Exceeding 20' and upto 40' in length	21.96	553.32
- Over 40' in length	29.28	737.92

- (b) This is to be replaced as follows:

Particulars	Foreign-going vessel (US \$)	Coastal vessel (in `)
Per FCL Container		Rate for coastal container is upto 60% (of the rate juxtaposed) calculated by taking into account the exchange rate fluctuation.
- Not exceeding 20' in length	14.64	
- Exceeding 20' and upto 40' in length	21.96	
- Over 40' in length	29.28	